भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 69

सोमवार, 04 दिसम्बर, 2023/13 अग्रहायण, 1945 (शक)

खराब होती सॉफ्टवेयर प्रणाली (ईपीएफओ)

69. श्री वी.के. श्रीकंदन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की पुरानी पड़ी और खराब हो रही सॉफ्टवेयर प्रणालियों को सुधारने और पुराने सर्वर जो संभवतः जनवरी 2024 तक काम करना बंद कर देंगे, को बदलने को अंतिम रूप देने में असमर्थ है;

(ख) क्या कर्मचारी भविष्य निधि ने इसके पुनर्स्थापन के संबंध में ध्यान में लाया है;

(ग) क्या यह उपर्युक्त में और विलंब से 21 लाख करोड़ रुपए के भारी-भरकम कायिक निधि वाले 25 करोड़ कर्मचारी भविष्य निधि खातों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सॉफ्टवेयर के साथ-साथ हार्डवेयर में भी सुधार लाने के लिए कदम उठाए हैं। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) बजट भी वर्ष 2019-20 में 48.67 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 283.3 करोड़ रुपए (बजट आवंटित) हो गया है। सर्वर सहित सभी हार्डवेयर रखरखाव के अधीन हैं।

इन्फ्रा-डेटाबेस लाइसेंस, कम्प्यूट (सर्वर) और स्टोरेज में हाल ही में वृद्धि की गई है। स्टोरेज संवर्धन नीति लागू कर दी गई है। 477 टेराबाइट का स्टोरेज एरिया नेटवर्क (एसएएन) स्टोरेज सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से खरीदा गया है और इसे डेटा सेंटर, वैकल्पिक डेटा सेंटर और राष्ट्रीय डेटा सेंटर में स्थापित किया गया है।

आईटी हस्तक्षेपों और संवर्द्धनों के साथ नियमित निगरानी के परिणामस्वरूप सदस्यों को दक्षता और अंतिम प्रदायगी में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जैसा कि निम्नलिखित द्वारा प्रदर्शित किया गया है:

(i) वर्ष 2021-22 में समय पर दावा निपटान 96.43% से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 98.92% हो गया है।

(ii) शिकायत निवारण समय/अवधि को आधा कर 06 दिन कर दिया गया है।

(iii) दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 31.10.2023 तक क्षेत्रीय कार्यालय आवेदनों में लेनदेन की मात्रा, जिसमें 1,07,277 करोड़ रुपए की राशि के 261.47 लाख दावों को संसाधित किया गया है, जो परिचालन दक्षता को दर्शाता है।

(iv) वर्ष 2022-2023 में 588 लाख दावों का निपटान किया गया है, जो वर्ष 2019 में निपटाए गए दावों की तुलना में 95% अधिक है।

*****